संपादकीय

सत्यता सामने लाईए तथा अराजकता पर लगाम लगाइये

श्री ए. राजा, मंत्री के त्यागपत्र के पश्चात श्री कपिल सिब्बल, मानव संसाधन मंत्री ने संचार तथा आईटी मंत्रालय का कार्य भार भी ग्रहण किया है। यह एक चुनौतीपूर्ण जिम्मेदारी है क्योंकि इस समय विभाग भ्रष्टाचार तथा अराजकता से ग्रसित है। इन्हें यह विरासत भूतपूर्व संचार मंत्री से प्राप्त हुई है जिसे शीघ्रता से दूर करना आवश्यक है। श्री सिब्बल एक प्रख्यात एडवोकेट के साथ–साथ चरित्रवान, निष्ठावान तथा अत्यंत गतिशील व्यक्ति है। एनएफटीई उनका स्वागत करती है तथा बीएसएनएल के विकास विस्तार में सहयोग देने का विश्वास दिलाती है।

श्री राजा की विदाई को अचानक की संज्ञा दी जा सकती है परंतु इसकी पूर्ण आशा थी। उन्होंने रिपोर्ट के अनुसार पद का दुरूपयोग करके देश को अरबों रूपये का चूना लगाया है। देश की आजादी के पश्चात् यह सबसे बड़ा घोटाला है। देश को 1.76 लाख करोड़ रूपयों की चपत लगी है। सीबीआई ने अदालत में केस दाखिल कर रखा है। सीएजी ने स्पष्ट रूप से अपने रिपोर्ट में कहा है कि वर्ष 2008 में 2जी स्पेक्ट्रम के आवंटन में नियम, कानूनों की धज्जी उड़ायी गई है। इस कारण राजा का ताज छिन गया। इससे दूरसंचार की छवि धूमिल हुई है। वर्ष 2008 में चौथा वेरीफिकेशन हुआ था। एनएफटीई अपनी सभाओं, प्रेस विज्ञप्ति तथा टी वी चैनलों के माध्यमों से उस समय भी स्पेक्ट्रम घोटाले में सीबीआई जांच की मांग की थी। परंतु इसके ठीक विपरीत मान्यता प्राप्त *संघ अपने पत्र द्वारा राजा जी को घोटाले में "क्लीन चिट" दिया। ट्रेड यूनियन्स की भूमिका एक सजग प्रहरी की होती है परंतु जांच एजेन्सी की कदापि नहीं। "क्लीन चिट" देना तथा दोषी पाना जांच एजेंसी का कार्य है। क्लीन चिट देने से काले कारनामों में वृद्धि हुई है।* श्री राजा के कार्यकाल में सीबीआई ने संचार भवन के दफ्तरों को भी सील किया जो कि पूर्व में कभी भी नहीं हुआ है। एनएफटीई आज भी दृढ़ है कि ऐतिहासिक घोटाले की जांच हो तथा दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जाय। सूत्रों के अनुसार तत्कालीन संचार मंत्री का कार्यालय निरंतर बीएसएनएल के कार्यों में दखल देता रहा है। प्रबंधन को उपकरणों तथा पुरानी तकनीकी को लेने के लिए दबाव डाला जाता था। विवादित तथा कलंकित अधिकारियों को लुभावने स्थान पर लुभावने पोस्टिंग दिए गए हैं। इन कार्यों में सीवीसी के दिशा–निर्देशनों की भी धज्जी उड़ायी गई है। अधिकारियों को निर्धारित अवधि के पश्चात् भी पद पर रोका गया है। ***आज बीएसएनएल में नियमित सीएमडी, निदेशक (इंटरप्राईज) तथा निदेशक (वित्त) नहीं है। प्रबंधन बिल्कुल पंगु है।***

हम आशा करते हैं कि नए संचार मंत्री तथ्यों को सामने लाएंगे तथा अराजकता को समाप्त करेंगे तथा स्वच्छ एवं सुंदर वातावरण शीघ्र स्थापित करेंगे।

प्रबंधन को पत्र

बोनस का भुगतान

टीएफ–7/1 दिनांक 12.11.2010 सी एमडर, बीएसएनएल को

संघ को ज्ञात हुआ है कि प्रबंधन ने डियूटी जी एम तथा अन्य ज्येष्ठ अधिकारियों को रूपया 17,000/– से लेकर रूपया 32,00/– का ब्लैकबेरी मोबाइल सेट खरीदने का सैन्कशन दिया है। इसके अतिरिक्त पुनः पांच अधिकारियों को विदेश यात्रा पर भेजा जा रहा है। इससे कम्पनी का करोड़ों रूपया व्यय होगा। हमें पता चला है कि बोनस का मुद्दा बीएसएनएल बोर्ड में प्रस्तुत हो रहा है।

अतः उपर्युक्त परिपेक्ष्य में आपसे अनुरोध है कि कर्मचरियों के बोनस का भुगतान सुनिश्चित करें। कर्मियों को बोनस से वंचित उचित नहीं होगा।

समस्याओं का समाधान हो

टीएफ–38/6 दिनांक 9.11.2010 चीफ लेबर कमिशनर, नई दिल्ली को

समस्याओं तथा मांगों की एक सूची संलग्न कर रहा हूं। इन मांगों का समाधान प्रबंधन द्वारा नहीं किया जा रहा है।